

‘हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं’, भाषा विवाद पर बोले राज ठाकरे

एजेंसी मुंबई । महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और एज ठाकरे ने मराठी एकता पर मुंबई के वर्ली डोम में एक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर राज ठाकरे ने कहा, मैंने कहा था कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। हम 20 साल बाद एक मंच पर आए हैं। हमारे लिए कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सिर्फ

महाराष्ट्र और मराठी हमारे लिए एजेंडा है।राज ठाकरे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम शांत हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से डरते हैं। मुंबई को महाराष्ट्र से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हिंदी अच्छी भाषा है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता है। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। मनसे अध्यक्ष ने कहा, एक



कहां से आया? ये सिर्फ केंद्र सरकार से आया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अंग्रेजी में है, किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों? जब महाराष्ट्र जागता है, तो दुनिया देखती है। मराठा शासन हिंदी भाषा से भी पुराना है। मेरे पिता और बाला साहेब ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी। क्या आपने कभी उनके मराठी या

वे यह मुद्दा उठा रहे हैं कि ठाकरे के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ें हैं। यह क्या बकवास है? कई भाजपा नेताओं ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन किसी को उनके हिंदुत्व पर संदेह है। उन्होंने कहा, दक्षिण में स्टालिन, कनिमोड़ी, जयललिता, नारा लोकेश और सूर्या, सभी ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है। बालासाहेब और मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है,

लेकिन वे मातृभाषा मराठी के प्रति बहुत संवेदनशील थे। बालासाहेब ठाकरे ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा से समझौता नहीं किया। किसी को भी मराठी को तिरछी नजर से नहीं देखना चाहिए।वहीं, उद्धव ठाकरे ने मंच पर आते ही कहा, राज ठाकरे ने बहुत कुछ बोल दिया, क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है?

पिनाराई विजयन उपचार के लिए अमेरिका रवाना

एजेंसी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन विशेष चिकित्सा उपचार के लिए सपत्नीक अमेरिका रवाना हो गये। श्री विजयन 10 दिनों के लिए वाया दुबई होते हुए आज तड़के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से रवाना हुए। वह डॉक्टर परामर्श और आगे के उपचार के लिए मिनेसोटा के रोचेस्टर में प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2018, 2022 और 2023 में मायो क्लिनिक में उपचार कराया था। विदेश दौरों के दौरान मुख्यमंत्री आमतौर पर जिम्मेदारियां नहीं सौंपते हैं। वह आमतौर पर ऑनलाइन मंत्रिमंडल बैठक में भाग लेते हैं और आवश्यक आधिकारिक मामलों को भी देखते हैं। मुख्यमंत्री के साथ पत्नी टी कमला और निजी स्टाफ सदस्य वी एम सुनीश भी गए हैं। श्री विजयन ने हालाकि नीलांबुर उपचुनाव से पहले अमेरिका जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चुनाव संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली व्यापक आलोचना और सार्वजनिक आक्रोश का सामना कर रही है। इस युष्मभूमि के बीच, हाल ही में कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में एक इमारत के ढहने से एक महिला की मौत की घटना पर विवाद जारी है। मुख्यमंत्री ने मृतक बिंदु के परिवार से मुलाकात नहीं की। इसके विपरीत, आमन चांडी फाउंडेशन (दिवंगत कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम पर) ने परिवार को उनके घर का निर्माण पूरा करने में मदद करने के लिए पांच लाख रुपये दिए हैं। श्री विजयन का प्रस्थान तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. हैरिस चिरायक्कल की एक वायरल फेसबुक पोस्ट के बाद हुआ है, जिसमें अस्पताल में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया गया था और राज्य के स्वास्थ्य ढांचे पर लोगों की चिंता बड़ गई थी। इस बीच, कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में दुःखद मौत ने राजनीतिक तूफान आ गया। जिससे विश्व ने स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था जम्मू से हुआ रवाना

जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा के 6979 तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था बम बम भाले के जयकारों के बीच दक्षिण कश्मीर हिमालय में भावती नगर स्थित यात्री निवास से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तीर्थयात्री 312 वाहनों के बड़े में जम्मू के आधार शिविर से रवाना हुए। उन्होंने कहा आज सुबह 6979 श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू बेस कैंप से कश्मीर में पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि 312 वाहनों के बड़े में 2753 तीर्थयात्री पहलगाम और 4226 तीर्थयात्री बालटाल के लिए रवाना हुए। इस बड़े में हल्के वाहन और भारी वाहन शामिल हैं। उपराज्यपाल मनाज सिन्हा ने जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद से नये जत्थे के रवाना होने के साथ ही अब तक कुल 24,528 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं।



पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथगोले और गोला-बारूद बरामद

पुंछ। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ के उपजिला सुरनकोट में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ कर हथगोले, गोला-बारूद समेत अन्य सामग्री बरामद की है। यह बरामदगी बेहामगला के पास मरह इलाके में की गई जहां पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी ठिकाने की तलाशी में तीन हथगोले, बीस गोलियां, वायर कटर, चाकू, चार्जिंग केबल और बैटरी जब्त की गईं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

आपकी प्रार्थनाओं का फल मिला, अभी 30 से 40 साल और जिऊंगा: दलाई लामा

धर्मशाला। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तेजिन ग्यात्सो ने कहा की कई बाध्यवाणिज्यों को देखते हुए, मुझे लगता है कि मुझ पर अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद है। मैंने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अभी 30 से 40 साल और जीऊंगा। धर्मगुरु ने कहा कि आपकी प्रार्थनाओं का अब तक फल मिला है और आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने यह बात उनके 90वें जन्मदिन से एक दिन पूर्व शनिवार को आयोजित प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए कही। दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस को लेकर शनिवार से दो दिवसीय समारोह शुरू हो गया है। समारोह के पहले दिन शनिवार सुबह मैकलेडॉजंग के मुख्य तिब्बती मंदिर च्गुलाखांग में उनकी लंबी उम्र के लिए दो दिवसीय धार्मिक प्रार्थना सभा शुरू हुई। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए द्वारा धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि हालांकि हमने अपना देश छो दिया है और हम भारत में निर्वासन में रह रहे हैं, लेकिन यहीं मैं जीवों को काफी लाभ पहुंचाने में सक्षम रहा हूं। मैं जितना हो सके जीवों को लाभ पहुंचाने और उनकी सेवा करने का इरादा रखता हूं।

वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी सफलता

विश्व बैंक ने दुनिया के सर्वाधिक ‘समतामूलक समाज’ में किया शामिल

एजेंसी नई दिल्ली । भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि आज यह सर्वाधिक समतामूलक समाजों में से एक भी है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बनाता है। यह भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ लोगों में समान रूप से पहुंच रहा है। इस सफलता के पीछे गरीबों को कम करने, वित्तीय पहुंच का विस्तार और कल्याण सह्यता को सीधे उन लोगों तक पहुंचाने पर लगातार नीतिगत ध्यान केंद्रित करना है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक



आवश्यकता है। गिनी सूचकांक यह समझने का एक सरल तरीका है कि किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसका मूल्य 0 से 100 तक होता है। 0 स्कोर का अर्थ पूर्ण समानता है, यानी आय आदि समान रूप से सभी लोगों के बीच वितरित हो रही है। 100

स्कोर का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय, संपत्ति या उपभोग है और दूसरों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए पूर्ण असमानता है। गिनी इंडेक्स जितना अधिक होगा, देश उतना ही असमान होगा। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। यह भारत को सापेक्ष रूप से दुनिया के सबसे समान देशों में से एक बनाता है। भारत का स्कोर चीन के 35.7 से बहुत कम है और अमेरिका से भी बहुत कम है, जो 41.8 पर है। यह हर जी7 और जी20 देश के भी प्रत्यक्षतः समान है, जिसमें से कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। भारत ‘सामान्य से कम’ असमानता श्रेणी में आता है, जिसमें गिनी स्कोर 25 से 30 के बीच है और यह ‘कम असमानता’ समूह में शामिल होने से थोड़ा ही दूर है, जिसमें स्लोवाक

नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार

सीबीआई और ईडी के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई कार्रवाई



एजेंसी नई दिल्ली। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है। नेहल मोदी पर पंजाब सूचकांक 28.8 पर मापा गया था और 2022 में 25.5 पर पहुंच गया।

आर्थिक अपराधों में सलिय होने के आरोप हैं। भारतीय एजेंसियों द्वारा उसे पहले से ही वांछित अपराधी घोषित किया जा चुका है। नेहल मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था। भारत की तरफ से अमेरिका के नेहल के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा गया था, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया।

राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत आक्षेपों के लिए कोई स्थान नहीं-शेखावत

एजेंसी जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत आक्षेपों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्री शेखावत यहां सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा कि श्री गहलोत द्वारा इसी सर्किट हाउस में उनकी दिवंगत माता पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, वे पूरी तरह निराधार और निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि अब श्री गहलोत ओख़्ता राजनीति पर उतर आए हैं और मीडिया के जरिए उन्हें संदेश भेज रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और परिवार की गरिमा से जुड़ा मामला मानते हैं। श्री शेखावत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ के आरोप लगाया बिचकूल भी शोभनीय नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री



आरोप लगाया चाहिए। श्री गहलोत द्वारा आपातकाल पर माफी मांगने से जुड़े सवाल पर भी श्री शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या जबरन नसबंदी के शिकार लोग उस अमानवीयता को भूल पाएंगे। क्या उनका कोई कसूर था। यह विषय क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने दो टुक कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा

गांधी ने केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट्टा। उन्होंने कहा कि लंबी गुलामी और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद भारत को आजादी मिली। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक इतिहास में देश की गौरवशाली परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे सजीव और प्रगतिशील संविधान है जो 1950 में लागू हुआ।

इसी के साथ नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई लेकिन देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। मौडिया पर घोषित और अघोषित प्रतिबंध लगाए गए। पत्रकारों को जेल भेजा गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी दबा दिया गया। श्री शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद के शासनकाल में हुए जनांदोलनों को नकारा नहीं जा सकता। वर्ष 1977 में जब जनता ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, तब जाकर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई।

योगी सरकार की पहल, बौद्ध-सिख श्रद्धालुओं के लिए दो तीर्थ यात्रा योजनाएं होंगी शुरू

एजेंसी लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की आस पूरी करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्राएं भारतीय संस्कृति में आत्मिक उथ्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को उनकी आस्था से जुड़े स्थलों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु ‘बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना’ और

सिख श्रद्धालुओं के लिए ‘पंच तख्त यात्रा योजना’ प्रारंभ की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं



को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आस्था के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा सुलभता से कर सकें। मुख्यमंत्री की मंशानुसार, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना

का उद्देश्य प्रदेश के हिंदू और बौद्ध श्रद्धालुओं को देश के विभिन्न भागों में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा



पूरी कराना है। मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के चयन में बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, पंच तख्त यात्रा योजना सिख श्रद्धालुओं के लिए होगी। इसके

अंतर्गत प्रदेश के सिख श्रद्धालुओं को भारत के पांच पवित्र ‘तख्त साहिब’ स्थल की यात्रा कराई जाएगी। सिख पंथ के लिए पवित्र पंच तख्त स्थलों में श्री आनंदपुर साहिब, पंजाब, श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर, पंजाब, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, पंजाब, श्री तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र, श्री हरमंदिर जी साहिब (पटना साहिब), बिहार, शामिल हैं। प्रस्तावित दोनों ही योजनाओं में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं के लिए आवेदन को शीघ्रता से प्रोसेस किया जाए और शीघ्रता से प्रोसेस किया जाए।

संभल सड़क हादसे में मृतकों की संख्या हुई आठ

निकलने के बाद सूरज की गाड़ी चली, जिसमें दूल्हा समेत 10 लोग बैठे थे। गांव के कुछ ही दूर जनता इंटर कॉलेज की दीवार पर दूल्हे की तेज रफ्तार कार टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी और उसमें बैठे दूल्हा समेत 5 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और राहत बचाव



करते हुए 5 अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें कुछ की हालत नाजुक देख अलीगढ़ रेफर किया गया। घायलों को बाहर निकालने में पुलिस को क्रेन की मदद ली। इसी बीच सूचना पर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, सीओ और सीएमओ समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की गई। एसपी

ने बताया कि दुर्घटना का कारण कार पर से चालक का नियंत्रण खोना है। मौके पर दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल में जिन तीन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान दूल्हे की बहन मधू, चालक रवि और ग्रामीण सचिन के रूप में हुई है। जो घायल है उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

भारथी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कन्दरी, माण्डर, राँची के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन



दिव्य दिनकर संवाददाता

मांडर - आज दिन शनिवार को भारथी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कन्दरी, माण्डर, राँची के एन.एस.एस. यूनिट द्वारा महाविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए गांव ह्करकराह्म एवं आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के बी०एड० सत्र 2024-26 प्रथम वर्ष एवं डी.एल.एड के सभी छात्र-छात्राई,व्याख्यातागण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत मुड़मा के मुखिया श्री बंधन उरांव थे।कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० दिपाली पाराशर एवं मुख्य अतिथि मुखिया श्री बंधन उरांव जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 40-50 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम कन्दरी के देवी मंडप में वृक्षारोपण कर-के किया गया, इसके साथ ही राजकीयकृत मध्य विद्यालय कन्दरी, मुड़मा पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान करकरा, के साथ ही ग्रामीण- श्री सुरेश ठाकुर, श्री आदित्य कुमार ठाकुर, सुखदेव उरांव, एतवा उरांव, कादीर अन्सा-री, फिरोज अंसारी आदि के यहाँ प्रमुख रूप से वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व इस प्रशिक्षण महाविद्यालय के एन.एस.एस. कार्यक्रम पदाधिकारी श्री विवेक राज जायसवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महा-विद्यालय की प्राचार्या, सभी व्याख्यातागण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र-छात्राई, पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण सक्रिय रूप से भाग लिए।

समाजसेविका प्रिया सिन्हा ने मनाया

अपना प्रेरणादायक जन्मदिन

दिव्य दिनकर संवाददाता

राँची - प्रसिद्ध समाजसेवी एवं भाजपा नेत्री प्रिया सिन्हा ने मनाया अपना शानदार और प्रेरणादायक जन्मदिन। जन्मदिन के दिन सर्वप्रथम सुबह मे ईश्वर के रूप में अपने पिता के घर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया,उसके बाद कुछ मंदिरों में जाकर बाहर बैठे दरिद्र नारायण के बीच भोजन का वितरण,गोशाला में जाकर गौ माता को हरी सब्जी खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया।इसके बाद रात्रि मे बेटी समीक्षा,पति विजय सिन्हा जी एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति मे केक काटकर खुशियां मनाई।मौके पर उपस्थित शहर की प्रसिद्ध गायक जोड़ी कुमार गहलोत एवं कविता होरो ने अपने गायन से सभी अतिथियों का भरपूर मनोरंजन किया वहीं अतिथियों के रूप में उपस्थित समाजसेवी गिरिजा शंकर पेडीवाल,भाजपा नेता रोहित शास्त्री,नम्रता सोनी, ज्योति सिन्हा,गायिका कंचन बाला,समाजसेवी पूनम बाला, प्रियंका जायसवाल,जितेंद्र बर्नवाल,पब्लिक न्यूज के प्रभात कुमार राजन आदि आदि ने उज्ज्वल भविष्य,लंबी उम्र की कामना करते हुए प्रिया सिन्हा को जन्म दिन की बधाई दिए।



राजकीयकृत प्राथमिक स्कूल मांडर से ताला तोड़कर चोरी

दिव्य दिनकर संवाददाता

मांडर -प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थित राजकीयकृत प्राथमिक स्कूल मांडर में शुक्रवार की रात को चोरी की घटना हुई। चोर विद्यालय के मध्यान्ह भोजन के स्टर रूम के दरवाजे का ताला तोड़ वहां से दो भरा हुआ गैस सिलेंडर व तीन बोरा चावल चुरा ले गये. चोरी की सूचना मांडर थाना को दे दी गयी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कांग्रेस कार्यालय में संगठन सृजन के तहत सांगठनिक स्वरूप की समीक्षा बैठक आयोजित



देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी जिलाध्यक्ष वासुकी पंडित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिंह ने भाग लिया तथा विशेष रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रो उदय प्र-काश भी शामिल हुए। बैठक में संगठन सृजन तहत सांगठनिक स्वरूप का समीक्षा किया गया। तदुपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने सेवा दल के संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम संचालित है। इस तहत कांग्रेस सेवादल के साथ सभी फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन का भी संगठन को सशक्त बनाने का काम चल रहा है। सेवा दल के संगठन को जिला में मजबूत करने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत तक सेवा दल का विस्तार करना है। यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना है। जिलाध्यक्ष प्रो उदय प्रकाश ने कहा कि देवघर में सेवा दल का संगठन पूर्व से मजबूत है तथा इसे और भी मजबूत करना है। इसके लिए रणनीति के तहत का करें। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अवधेश प्रजापति, जिला महासचिव-सह-प्रवक्ता दिनेश कुमार मंडल, सेवा दल के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश यादव,कमल वर्मा,भोला सिंह,अमोद कुमार राव,विपुल पंडित, सत्यनारायण ठाकुर,मैनेजर सिंह,भागीरथ यादव,अर्जुन सिंह,उमेश यादव, वीरेंद्र सिंह, सुरेश पंडित,उमेश यादव,मनोज यादव,दिनेश दास, मनोज सोरेन,मुन्ना कुमार यादव, प्रेमलता देवी,राधा पाल,विभा देवी,एन एस यू आई नगर अध्यक्ष प्रियांशु कुमार,अटल मिश्रा, प्रियांशु सिंह,संतोष यादव, गोलू सिंह आदि मौजूद थे। आदि मौजूद थे।

पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचकर शिवू सोरेन के स्वास्थ्य की ली जानकारी

झारखंड के विकास कार्यों को लेकर सौरभ नारायण सिंह और सीएम हेमंत सोरेन के बीच हुई चर्चा

हजारीबाग

हजारीबाग सदर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ नारायण सिंह ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में झारखंड के संरक्षक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक बाबा शिवू सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने बाबा के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान सौरभ नारायण सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की, जो अपने पिता बाबा शिवू सोरेन के साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से बाबा के इलाज की विस्तृत जानकारी ली और कहा

कि बाबा झारखंड की आत्मा हैं, उनका स्वास्थ्य रहना पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। पूर्व विधायक ने कहा कि बाबा शिवू सोरेन झारखंड की राजनीति के एक स्तंभ हैं। उनके संघर्षों से यह राज्य बना है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ और इस कठिन समय में पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। बता दें कि कुछ दिनों से बाबा शिवू सोरेन अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और लगातार उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौरभ नारायण सिंह



की इस मुलाकात को राजनीतिक से

ज्यादा सामाजिक और मानवीय जुड़ाव

के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली स्थित सर गंगाराम हॉस्पिटल में झा-रखंड के संरक्षक बाबा शिवू सोरेन से मुलाकात के बाद पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच राज्य के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने झारखंड के भविष्य, जनता की जरूरतें और सरकार की प्राथमिकताओं पर आपसी विचार साझा किए। बातचीत के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शैक्षणिक संस्थानों की मजबूती, सड़क और यातायात सुधार, तथा यु-वाओं को रोजगार से जोड़ने जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि झा-रखंड एक संभावनाओं से भरा राज्य

है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राज्य में उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनकी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि झारखंड की जनता का भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, और हम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इस मुलाकात को झारखंड की राजनीति में एक सौहार्दपूर्ण संवाद और सहयोग की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। सौरभ नारायण सिंह ने यह भी कहा कि यदि सभी दल राज्य हित में साथ आएँ तो झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा सकता है। उन्होंने बाबा शिवू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ झा-रखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीद भी जताई।

अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की हुई बैठक लिए गए कई बड़े निर्णय

दिव्य दिनकर संवाददाता

चान्हो - चान्हो प्रखण्ड के बलसोकरा अंसारी मोहल्ला अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की बैठक बीती रात 11 बजे तक चली बैठक के अध्यक्षता अंजुमन के सदर रहमतुल्लाह अंसारी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से समाज में हो रही बु-राइयों के रोकथाम पर चर्चा की गई साथ ही समाज में शिक्षा की कमी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कमेटी ने मोहल्ला और समाज में नशा खोरी करने वालों के खिलाफ मुहिम चला कर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। वहीं कमेटी के बुलाए गए बैठकों में जो लोग शामिल नहीं होते हैं उनके खिलाफ भी कड़ा निर्णय लिया गया है इसमें कहा गया है कि



किसी भी मामले पर कमेटी शामिल नहीं होगी वहीं जो नशा महल्ले के लोग नशा कर रहे हैं उनके परिवार के मुखिया को बुलाकर सख्त वार्निंग दिया जाएगा फिर भी आगे वे व्यक्ति नशा करता हुआ पाया तो उसके परि-रवार से सभी मामलों पर कमेटी दुरी बना लेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से हाजी तफज्जुल अंसारी,मौलाना शा-हाजहां मेराजअंसारी, जमील अख्तर,हाफिज शमशुल हक, हाफिज अब्दुल मौजिद, हाफिज रेयाज,समशद अंसारी,हसीब अंसा-री,अब्दुल रशीद,मोहम्मद अजहर,इकबाल अंसारी,परवेज अंसारी,मंजूर अंसारी,जमील अंसा-री,समील्लाह अंसारी, अफसर अंसा-री सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सुनील खवाड़े देवघर ट्रॉफी सीजन वन का हुआ भव्य शुभारंभ

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

आईपीएल के तर्ज पे टेनिस बॉल में भी देवघर के इतिहास में पहली बार केकेएन स्टेडियम में शुरू हुआ ऐसा टूर्नामेंट । मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार और डॉ सुनील खवाड़े द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया इस टूर्नामेंट का शुभारंभ। विशिष्ट अतिथि में देवघर जिला हैंड बॉल संघ के चेयरमैन संजय मालवीय, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह , डीएसए सचिव आशीष झा,देवघर जिला ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा,बजरंगी महथा,उपस्थित थे।।हस टूर्नामेंट में टोटल छह टीम भाग ले रही है। इस प्रकार है पी वी आर पैथर, कैलाश फाइटर, स्टाइलिश 11,मुकेश प्लावर, मां मनसा ऑरेंज लायन, लिटिल पैर-डाइज 11 , यह टूर्नामेंट 5 जुलाई से 16 जुलाई 2025 तक चलेगा।।हस्-रका ऑक्शन देवघर के उत्सव प्लेस में 29 जून को कराया गया था जिसमें सभी टीम ओर आईकों खिलाड़ी मौजूद थे आइकों की लिस्ट कुछ एक प्रकार है अकित पांडेय, मनीष यादव, रंजीत यादव, संजीव झा, शालू मिश्रा, उज्जवल राय



इस ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी विककी सिंह (11000) की राशि में जिसको सर्वाधिक बोली लगाकर पी वी ए पैथर ने अपने साथ जोड़ा है।। डॉक्टर सुनील खवाड़े ने कहा कि इस टूर्नामेंट को कराने का मकसद है टेनिस बॉल क्रिकेट जो अभी पूरे विश्व में एक स्थान ले रहा है , जैसे कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) और टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग (टीबीसीपीएल), टेनिस बॉल का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं, वैसे ही यहां के खिलाड़ियों को एक

प्लेटफार्म देना।ताकि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बड़े स्तर पे भी कर सके।।और इस टूर्नामेंट के अगले सत्र का घोषणा भी किया की अगला सीजन परवरी में और भी भव्य तर-िके से कराया जाएगा।।मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में देवघर एक ऐसा जिला है जहां खेल के आयोजन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता और ये सब देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ सुनील खवाड़े और ड-ीएसए सचिव आशीष झा सहित संजय

मालवीय वीरेंद्र सिंह,नवीन शर्मा उनके टीम के कारण संभव हो पाता है।हस तरह का आयोजन ऐसे छोटे शहर में कराने के लिए आयोजकों का भी धन्यवाद दिया। इस टूर्नामेंट को अकित स्पोंटर्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का पहला मैच कैलाश फाइटर बनाम लिटिल पैराडाइज एलेवेन खेल गया जिसमें कैलाश फा-इटर टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 119 रन 4 विकेट खोकर बनाया।।लक्ष्य का पीछा करते हुए लिटिल पैराडाइज एलेवेन टीम ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य को पार कर लिए।।हसमें अक्षय 15 बॉल 39 रन बनाया । दूसरा मुकेश प्लावर और ऑरेंज लायन के बीच खेला गया जिसमें ऑरेंज लायन ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 146 रन बनाए जवाब में मुकेश प्लावर की टीम ने 7 विकेट खोकर 113रन बनाया और ऑरेंज लायन ने यह मैच 33 रन से जीता।। तीसरा मैच दर्शफैथर और स्टाइल एलेवेन के बीच खेल गया जिसमें pvr ने 105 रनों का टारगेट दिया जिसको स्टाइलिश 11 ने 108रन 3 विकेट के नुकसान पे आसानी से हासिल कर लिया।। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अकित स्पोंटर्स के नीरज झा,पंकज वाजोपेई, राजा लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के 29 वां स्थापना दिवस देवघर जिला कमेटी ने बहुत धूमधाम से मनाया

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

आज, दिनांक 05 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर देवघर जिला कमेटी एवं राजद परि-वार की ओर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष डॉ. फनी भूषण यादव, सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में राष्ट्रीय जनता दल के गौर-वशाली इतिहास, सामाजिक न्याय और समता के लिए इसके संघर्ष को याद किया गया। नेताओं ने पार्टी के संस्थापक श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद के योगदान को रेखांकित करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पार्टी की



प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ. फनी भूषण ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक है। हम अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हैं और समाज के हर वर्ग को साथ

लेकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मीडिया प्रभारी प्रमोद यादव ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनहित में कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक

काटकर राजद के 29वें स्थापना दिवस को हार्दिकता के साथ मनाया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और भविष्य में पार्टी को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भूतनाथ यादव जमीर अंसारी प्रमोद यादव कांति सिंह शंकर यादव मनोरंजन यादव विनोद यादव लालमोहन मांझी नेहा सिंह रूपेश कुमार सिंह अजय कुमार प्रकाश यादव दिवाकर महथा विजय यादव राम लखन यादव कांति सिंह सुशीला देवी पार्वती देवी जयंत पटेल प्रकाश महथा सुनील महाथा शिवनारायण रामानी बलदेव यादव मनोज यादव सुशीला देवी सहित दल सेकड़ों नेताओं ने भाग लिए

वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी के तस्करी का किया पदार्पण चालक सहित वाहन हिरासत में



रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़:हिरणपुर डांगपाड़ा चौक निकट वन कर्मियों ने शनिवार को लक-ड़ी से लदे एक ऑटो को पकड़ा। जिसमें 15 पीस चिरान किया हुआ महुआ वृक्ष की लकड़ी पाया गया। अवैध लकड़ी को वाहन में लोड कर डांगपाड़ा के रास्ते शहरग्राम ले जाया जा रहा था, जिसे मौके पर ही फोरेस्टर बबलू देहरी एवं वन विभाग की टीम के द्वारा धर दबोचा. मौके पर ही पकड़े गए चालक की पहचान श्याम साहा के रूप में हुई वाहन चालक श्याम के द्वारा लकड़ी को शहरग्राम निवासी रंजीत साहा के पास पहुंचा था। इस सम्बंध में फोरेस्टर बबलू देहरी ने बताया कि लकड़ी अवैध रूप से ले जाया जा रहा था , जिसे जप्त किया गया है। वहीं चालक को भी हिरासत में लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लकड़ियों की अवैध तस्करी किसी भी हालात में चलने नहीं दी जाएगी। बहरहाल लकड़ियों की अवैध कारोबार बंदस्तूर जारी है। वहीं जंगलों की भी कटाई की जा रही है। इस प्रति विभाग को सख्त रख अपनाना आवश्यक है।

राम विलास पासवान की 79वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि व भव्य आयोजन

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवघर के बाबा होटल में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के तत्वावधान में जन नेता, जन सेवक, समाज सुधारक एवं पद्मभूषण स्व. राम विलास पासवान की 79वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवघर जिला अध्यक्ष कुमार सौरभ ने की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों और गणमान्य नागरि-रकों ने स्व. रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आशुतोष मिश्रा ने अपने संबोधन में स्व. राम विलास पासवान के सामाजिक न्याय, दलित उत्थान और कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का मसीहा बताया। वरिष्ठ नेता लाल मणि झा ने कहा कि रामविलास पासवान का जीवन सम्पन्न, सामाजिक समरसता, समानता और जनसेवा को समर्पित था। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख नेताओं में आशुतोष मिश्रा प्रदेश महासचिव, लाल मणि झा प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष (युवा प्रकाष्ठ)सह स्थंाल पराना प्रभारी, ठाईगर रमेश सिंह प्रदेश सचिव, विककी कुमार मदनपति जिला अध्यक्ष आई .टी. सेल, नगर अध्यक्ष राजीव ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल रहे। सभी ने उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया और अंत में सभी को सामूहिक रूप से जलपान कराया गया।



वोटर सूची संशोधन संबंधी सवालों का शीघ्र हो समाधान

>> विचार

“मतदाता सूचियों को संशोधित करने का विचार नया नहीं है। वास्तव में, 2003 की कवायद के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कई पूर्वीतर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर गहन संशोधन प्रक्रिया चलाई थी। हालांकि, तब इन संशोधनों को चुनावों से ऐन पहले नहीं करवाया गया था, न ही चुनिंदा मतदाता समूहों के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इससे पहले भी, बिहार सहित 20 अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसी किस्म की कवायद हुई थी। इससे पहले भी, बिहार सहित 20 अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसी किस्म की कवायद हुई थी। एसआईआर मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का आधारभूत अवयव है झ्र विशेषतया बड़े पैमाने पर हुई कवायदों में जैसे परिसीमन, किसी क्षेत्र में उथल-पुथल उपरांत शांतिकाल या डिजिटलीकरण।

एसवाई कुरैशी जब भारत के चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन कुछ महीने पहले मतदाता सूचियों में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) किए जाने की घोषणा कर दी, तो इससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गईं। हालांकि चुनाव आयोग इस कवायद का बचाव संवैधानिक अनिवार्यता बताकर कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह जरूरी है कि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। आयोग के मुताबिक, वर्तमान संशोधन का उद्देश्य सूचियों में सुधार करके यह प्रावधान यकीनी बनाना है। इस विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूचियों में जिनका नाम शामिल था, उन्हें सत्यापित मतदाता माना जाएगा। अतीत में भी चुनाव आयोग उन जगहों पर गहन संशोधन करने का आदेश देता आया है, जहां उसे मतदान सूची की विश्वसनीयता संदिग्ध या पुरानी लगे। हालांकि, जिन लोगों का नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुआ है या जिन्होंने नाम कभी शामिल नहीं कराया- उन्हें अब नागरिकता की स्व-घोषणा और अन्य सहायक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र या माता-पिता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके पीछे घोषित इरादा चुनावी डेटाबेस अपडेट व शुद्ध करना है। लेकिन, ईमानदारदिखने वाली अनेक अन्य प्रक्रियाओं की तरह यहां भी छिपी चतुर्थाई विवरण में स्पष्ट हो जाती है। मतदाता सूचियों को संशोधित करने का विचार नया नहीं है। वास्तव में, 2003 की कवायद के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कई पूर्वीतर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर गहन संशोधन प्रक्रिया चलाई थी। हालांकि, तब इन संशोधनों को चुनावों से ऐन पहले नहीं करवाया गया था, न ही चुनिंदा मतदाता समूहों के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इससे पहले भी, बिहार सहित 20 अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसी किस्म की कवायद हुई थी। एसआईआर मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का आधारभूत अवयव है झ्र विशेषतया बड़े पैमाने पर हुई कवायदों में जैसे परिसीमन, किसी क्षेत्र में उथल-पुथल उपरांत



शांतिकाल या डिजिटलीकरण। 2003 व 2004 के बाद से वार्षिक सारांश संशोधन सामान्य प्रक्रिया बन गये। साल 2004 के बाद किसी भी राज्य को चुनाव आयोग के सचेत निर्णय चालित गहन संशोधन नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर-घर सर्वेक्षण के अलावा वार्षिक सारांश रिपोर्ट पर्याप्त थी। स्थापित प्रथा से विचलन व जिस वक्त यह कवायद की जा रही है, वह बिहार में इसे विवादस्पद बनाता है। निस्संदेह, मतदाता सूचियों को नियमित अपडेट किया जाना चाहिए झ्र लेकिन बिहार में जैसे बाद-ग्रस्त, उच्च-प्रवासन वाले राज्य में मतदान से बमिश्रित चार महीने पहले ऐसा करना इसे बहुत मुश्किल काम बनाता है। चिंता का की नहीं; बल्कि व्यावहारिकता व कार्यान्वयन से उपजने वाली राजनीतिक हस्यावली को लेकर है। मूलतः, यह संशोधन प्रमाण पेश करने का भार मतदाता पर डाल रहा है। जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अब दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपनी प्रमाणिकता

साबित करनी होगी।। सैद्धांतिक रूप में भले यह उचित लगता हो, किंतु व्यावहारिक पटल पर इससे उन लोगों को मताधिकार से वंचित करने का खतरा बन जाता है, जिनकी सरकारी कागजात पूरा करने की दरकारों में फंसे की गुंजाइश सबसे अधिक है, मसलन, प्रवासी मजदूर, दलित, आदिवासी, शहरी गरीब, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग और महिलाएं- जिनमें से अधिकांश के पास जन्मप्रमाण पत्र या माता-पिता के दस्तावेज नहीं। ऐसे लोगों के लिए उनका नाम पिछली मतदाता सूची में होना पर्याप्त माना जाना चाहिए था, खासकर अब जबकि डिजिटलीकरण काफी उन्नत है। यहां पर असम की एनआरसी प्रक्रिया के साथ समानता करने से बच नहीं सकते। वहां भी, ऐतिहासिक दस्तावेजों की अनिवार्यता पूरी न किए जाने के कारण लगभग बीस लाख लोग मतदान सूची से बाहर हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर गरीब हैं। जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया है-न कि नागरिकता की पड़ताल।

इस मुद्दे को और जटिल बनाता है, व्यापक परामर्श का अभाव। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन संशोधन को बिना किसी पूर्व सूचना के या उनसे चर्चा किए बिना शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 2002-03 में 20 राज्यों में एसआईआर और पूर्वीतर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 2004 के संशोधन करने के दौरान, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ पहले मशविरा किया था। ऐसी कवायद जल्दबाजी में नहीं बल्कि अक्सर चुनावों से कई साल पहले की जाती थी, जिससे फीडबैक, जन जागरूकता मुहिम और पार्टियों की भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। विगत में चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन प्रकाशित किया और घर-घर जाकर सत्यापन में मदद करने के लिए करीब एक लाख बुध-स्तरीय अधिकारियों और इतने ही वालंटियर तैनात किये। सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसने स्पष्ट किया है कि 2003 की सूचियों में पहले से शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत

नहीं। वर्तमान में भले ही चुनाव आयोग ने दावों-आपत्तियों की प्रक्रिया खोल दी व राजनीतिक दलों से बृथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने को भी कहा है। ये सभी कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन संशोधन प्रक्रिया की चिंताओं का निवारण करने में पर्याप्त नहीं। बेशक विशेष गहन संशोधन का कानूनी आधार मजबूत है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21, मतदान सूचियों को वक्त मुताबिक संशोधित करने का समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी इन मामलों में आयोग की स्वायत्तता की पुष्टि की है। लेकिन लोकतंत्र में कानूनी अवयव एकमात्र पैमाने नहीं होते बल्कि नैतिक वैधता व जनता का भरोसा उतने ही मायने रखता है। चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए झ्र बल्कि उसे निष्पक्षता से काम करते हुए दिखना भी चाहिए। गहराये राजनीतिक धुवीकरण और संस्थानों के प्रति अविश्वास के बढ़ते माहौल के बीच सहानुभूति और स्पष्टता की कमी होने पर नैकनीयत कार्यों को भी गलत समझा जा सकता है। आयोग को दस्तावेजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही इसको पहले उन राज्यों में शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जहां चुनाव 2-3 साल बाद होने हैं। ऐसे वक्त में, संस्थान यह वास्ता देकर कि वह तो सिर्फ कानून का पालन करवा रहा है, अपनी विश्वनीयता खो सकते हैं। बाकियों की तरह, बिहार के मतदाता भी,स्वच्छ मतदाता सूची के हकदार हैं झ्र लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के बाहर छूट जाने की एवज पर नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संक्षेप के रूप में, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक का वोट देने का अधिकार न केवल सुरक्षित रहे बल्कि वह सम्मानित भी महसूस करे। जब मतदान का अधिकार संवैधानिक गारंटी के बजाय विशेषाधिकार की तरह लगने लगे, तो लोकतंत्र की भावना अपने आप सिक्कड़ जाएगी।

(लेखक भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।)

संपादकीय

बिहार के मतदाता सूची सुधार में कहीं गरीब तो वंचित न हो जाए

इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के त्रम में किसी मजबूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं ! बिहार के विपक्षी दलों ने इस पर कई सवाल उठाए हैं मतदाता सूची को त्रुटियों से रहित बनाने का काम निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाने के भी अपने आधार हैं। आयोग की ओर से इस सूची में बने रहने के लिए जिन स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, बिहार के बहुत सारे लोगों को लिए यह एक बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी-खासी होगी, जिनके पास खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे और अगर वे इन्हें नए सिरे से बनवाने के काम में लगेंगे तो इसके लिए समय की जरूरत होगी। जबकि बिहार में अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए महज एक माह का समय दिया गया है। स्वाभाविक ही इस समय के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, अगर उसमें शामिल होने के पात्र लोग किन्हीं वजहों से छूट गए, तो उनके दावों और आपत्तियों को निपटने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? यह छिपा नहीं है कि बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसे गरीब और कम शिक्षित लोगों की है, जिनके पास सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होंगे। खासतौर पर जन्म पंजीकरण के मामले में काफी पीछे रहने की वजह से बहुत कम लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं। हालांकि हाशिये के समुदायों के ज्यादातर लोगों की पहुंच आधार और राशन कार्ड तक है, जिनकी मांग आमतौर पर हर चीज के लिए की जाती है। मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से इन्हें स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ताजा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इस दायरे में आएंगे, उनके लिए भी निर्धारित दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई जा रही हैं और विपक्षी दल इस कवायद को समान अवसर के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नए नियमों की वजह से किसी भी वैध मतदाता के मतदान का अधिकार का हनन न हो।

प्रमोद भागवत

भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले व्यापार समझौता होना है। यदि भारत अमेरिका की शर्तें नहीं माना है तो 9 जुलाई से टैरिफ यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर 10 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत हो जाएगा। भारत चाहता है कि जल्द अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए। लेकिन अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए चाहता है कि भारत में उसे कृषि और डेयरी उत्पाद बचने की अनुमति दी जाए। चीन ने अमेरिकी उत्पात खरीदने से मना कर दिया है। भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद अमेरिका के लिए कृषि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं है। दरअसल भारत की 70 करोड़ से भी अधिक आबादी कृषि, दूध और मछली व अन्य समुद्री उत्पाद पर आश्रित है। इन उत्पादों से जुड़े लोग आत्मनिर्भर रहते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से मुफ्त अनाज, खाद्य सब्सिडी और किसानों को छह हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देती है। भारत की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्था के मूल आधार कृषि और उससे जुड़े उत्पाद हैं। अब अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर व्यापक दबाव बनाकर द्विपक्षीय बातचीत करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तो खुले ही उत्पादों पर शुल्क भी कम करे। यदि भारत कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए दबाव बनाएंगे। यूरोपीय संघ चीज व अन्य दुग्ध उत्पादों पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जॉर्ज लुटेंस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीन ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत में इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता में



शामिल करने की बात कही है। किंतु भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। इसीलिए भारत के जितने भी पर्व हैं, उनका पंचांग कृषि पद्धति पर ही आधारित है। जबकि अमेरिका व यूरोपीय देश कृषि को मुनाफे का उद्योग मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो उसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत है। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आकर्षक बाजार के रूप में देखते हैं। जबकि भारत अपने कृषि क्षेत्र को मध्यम से उच्च शुल्क की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संरक्षित किए हुए है ताकि अपने किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कृषि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है कि आयात प्रतिबंधों और शुल्कों को कम करना। कृषि को बाहरी

सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा, सरसे खाद्य उत्पादों का भारत में आना, यह खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। ऐसा ही दबाव भारत पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने जेनेवा में 2022 में हुई बैठक में बनाया था। यहां तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृषि अनुवृत्ति (सब्सिडी) का जबरदस्त विरोध किया था, ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद करे। यही नहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर के 81 करोड़ लोगों को जो अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आपत्ति जताई थी। देश की करीब 67 फीसदी आबादी को मुफ्त अनाज मिलता है। इस कल्याणकारी योजना पर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च सब्सिडी के रूप में प्रति वर्ष होता है। परंतु भारत ने अपने किसान और गरीब आबादी के हितों से समझौता करने से साफ इंकार कर दिया था। इसे डब्ल्यूटीओ के तय नियमों का खुला

उल्लंघन करार दिया गया था। क्योंकि नियमानुसार अनाजों के उत्पादन मूल्य पर 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत इससे कई गुना ज्यादा सब्सिडी देता है। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत गेहूं व चावल के निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नेपाल के अलावा 68 देश भारत से गेहूं आयात करते हैं। भारत दुनिया के कुल 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है। किसी भी देश की प्रतिबद्धता विदेशी हितों से कहीं ज्यादा देश के किसान, गरीब व वंचित तबकों की खाद्य उत्पादन और सुरक्षा के प्रति ही होनी चाहिए। लिहाजा नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय से ही किसानों के हित में खुदे दिखाई दिए हैं। अगरव 2014 में इसी निवेदा में डब्ल्यूटीओ के हुए सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भागीदारी करते हुए 'समुचित व्यापार अनुबंध' ;ट्रेड फैलिथिडेशन एपीमेंटद्ध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस

करार की सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि संगठन का कोई भी सदस्य देश, अपने देश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य का 10 फीसदी से ज्यादा अनुदान खाद्य सुरक्षा पर नहीं दे सकता है। जबकि भारत खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की 67 फीसदी आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में है। इसके लिए बतौर सब्सिडी जिस धनराशि की जरूरत पड़ती है, वह सरकारी फसल उत्पाद मूल्य के 10 फीसदी से कहीं ज्यादा बैठती है। दरअसल सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10 फीसदी सब्सिडी का निर्धारण 1986-88 की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। इन बीते साढ़े तीन दशक में मंहगाई ने कई गुना छलांग लगाई है। इसलिए इस सीमा का भी निर्यात पर अनाजों के उत्पादन मूल्य पर 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत इससे कई गुना ज्यादा सब्सिडी देता है। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत गेहूं व चावल के निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नेपाल के अलावा 68 देश भारत से गेहूं आयात करते हैं। भारत दुनिया के कुल 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है। किसी भी देश की प्रतिबद्धता विदेशी हितों से कहीं ज्यादा देश के किसान, गरीब व वंचित तबकों की खाद्य उत्पादन और सुरक्षा के प्रति ही होनी चाहिए। लिहाजा नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय से ही किसानों के हित में खुदे दिखाई दिए हैं। अगरव 2014 में इसी निवेदा में डब्ल्यूटीओ के हुए सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भागीदारी करते हुए 'समुचित व्यापार अनुबंध' ;ट्रेड फैलिथिडेशन एपीमेंटद्ध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस

कॉलेजियम व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत



न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामांकन और सीनेट की मंजूरी से होती है, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई और गहन जांच शामिल होती है। हालांकि इस प्रणाली में भी

राजनीतिक दखल की आशंका बनी रहती है। यूरोप में, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम में, स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग जजों का चयन करता है, जिसमें योग्यता, अनुभव

और चरित्र की कठोर जांच होती है। भारत में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, जिसमें सरकार और

न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा। यह कहा जा रहा था कि संरचना में हस्तक्षेप की आशंका रहने से ऐसा आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरों में डाल सकता था। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत है। त्वयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने, अभ्यर्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच के स्पष्ट मानदंड तय हो ही एक स्वतंत्र नियमनी समिति गठित की जाए, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जांच करे। निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक भर्ती प्रक्रिया में योग्यता-आधारित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार शामिल करने होंगे। मोटे तौर पर भारत में जजों के चयन की ऐसी प्रणाली की जरूरत है, जो स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलन बनाने का काम करे। इससे न केवल त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा बल्कि न्यायपालिका को जनता की आस्था का प्रतीक भी बनाया जा सकेगा।

सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए दुबई में खोला प्रतिनिधि कार्यालय

एजेंसी नई दिल्ली। देश एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए दुबई में अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। सेल का मध्य पूर्व में पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय इसकी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेल के दुबई स्थित इस कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 3 जुलाई को किया। उद्घाटन अवसर पर भारत के महावाणिज्यदूत सतीश कुमार सिवन, सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रकाश, एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी, इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव वीके त्रिपाठी तथा सेल, इस्पात मंत्रालय, एनएमडीसी और मैकॉन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति थे। मंत्रालय के मुताबिक रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित दुबई कार्यालय सेल के इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने, उद्योग संबंधों को और परिपुष्ट बनाने और भारत-यूईई व्यापार संबंधों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में दुबई की भूमिका और निवेशक अनुकूल वातावरण इसे उभरते बाजारों में विस्तार के लिए एक आदर्श आधार बनाता है।

ऐडकाउंटी मीडिया की मजबूत एंट्री से खुश हुए निवेशक, लिस्टिंग के बाद पहले लोअर और फिर लगा अपर सर्किट

नई दिल्ली। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्युशंस मुहैया कराने वाली कंपनी ऐडकाउंटी मीडिया के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपनी ताकत दिखाई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 85 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी एंट्री 52.94 प्रतिशत लिस्टिंग गेन के साथ 130 रुपये के स्तर पर हुई। जोरदार लिस्टिंग के तुरंत बाद मुनाफा वसूली के चक्कर में बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में ये शेयर 123.50 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक पहुंच गया। इस जोरदार गिरावट के बाद खरीदारों ने भी लिवाली का जोर दिखाया, जिससे थोड़ी ही देर में ये शेयर लोअर सर्किट ब्रेक करके शानदार तेज दिखाते हुए 136.50 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 60.59 प्रतिशत का फायदा हो गया है।

ऐडकाउंटी मीडिया का 50.69 करोड़ रुपये का आईपीओ 26 जून से एक जुलाई के बीच सप्सक्रािशन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिसॉप्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 273.08 गुना सप्सक्राइब हो गया था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 137.33 गुना सप्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 555.79 गुना सप्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 229.37 गुना सप्सक्राइब हुआ था।

स्टॉक मार्केट में नीतू योशी की धांसू एंट्री, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

नई दिल्ली। फेरस मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी नीतू योशी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश किया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 75 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी एंट्री 40 प्रतिशत लिस्टिंग गेन के साथ 105 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के तुरंत बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण ये शेयर गिर कर 100.20 रुपये के स्तर पर पहुंच गया लेकिन थोड़ी ही देर बाद खरीदारी शुरू हो गई, जिसके कारण ये शेयर 110.25 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। इस तरह कंपनी के आईपीओ निवेशकों को पहले दिन के कारोबार में ही 47 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। नीतू योशी का 77.04 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 जून से एक जुलाई के बीच सप्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिसॉप्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 128.18 गुना सप्सक्राइब हो गया था।

सेबी का अमेरिकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ सख्त एक्शन, स्टॉक मार्केट में कारोबार पर लगी रोक

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अमेरिकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेन स्ट्रीट और इससे जुड़ी एंटीटो के भारतीय शेयर बाजार में एंट्री करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सेबी के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि वो जेन स्ट्रीट से 48.4 अरब रुपये यानी लगभग 570 मिलियन डॉलर की राशि जब्त करेगा। सेबी का कहना है कि ये राशि जेन स्ट्रीट ने अवैध रूप से अर्जित की गई थी। जेन स्ट्रीट को ये पैसा एक एक्को एकाउंट में जमा करना होगा। मार्केट रेगुलेटर के फैसले से अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म को जबरदस्त झटका लगा है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अभी सहमति नहीं, कुछ मुद्दों पर बातचीत बाकी

एजेंसी नई दिल्ली। अमेरिका के साथ भारत के अंतरिम व्यापार समझौते पर अभी सहमति नहीं बनी है। कृषि और वाहन क्षेत्र से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है। इसके 9 जुलाई से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर वार्ता अंतिम चरण में है। इसके निष्कर्ष की घोषणा 9 जुलाई से पहले होने की उम्मीद है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन से वापस आ गया है। इस समझौते पर बातचीत

अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए वाशिंगटन में थी। भारत ने

भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाना और गति एक साथ चल सकते हैं : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एजेंसी रियो डी जेनेरियो । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारत एक अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर प्रभाव पैदा करने वाले देश के रूप में अपनी दोहरी भूमिका के साथ न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आकांक्षाओं को साक्षा करने वाले सभी लोगों के लिए परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए मजबूत स्थिति में है। आधिकारिक यात्रा के दौरान चैलेंजेस फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल साउथ विषय पर फ्लैगशिप गवर्नर्स सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वित्तपोषित करना केवल धन जुटाने के बारे में नहीं है, यह निष्पक्षता, विश्वास और नेतृत्व

का निर्माण करने से भी जुड़ा है।

उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, "भारत के लिए, लाखों लोगों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा



और आजीविका तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकास में तेजी लाना आवश्यक है। साथ ही, हौदवेव, वॉटर स्ट्रेस और एक्ट्रीम वेदर की घटनाओं जैसे जलवायु संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं। भारत नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन

और प्रांत-स्तरीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।वित्त मंत्री ने कहा,

सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करें। वित्त मंत्री ने आगे कहा, जैसा कि हम 2030 के एजेंडे की ओर प्रयास कर रहे हैं, कोरोना महामारी के बाद विकासशील देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) के लिए वित्तपोषण का अंतर सालाना 4.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो महत्वकांक्षा और वास्तविकता के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। उन्होंने कहा, भारत एक अनाखे चोराहे पर खड़ा है। एक अरब लोगों की आकांक्षाएं तेजी से बदलते ग्रह की अनिवार्यताओं के साथ मिलती हैं। भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाना और गति एक साथ चल सकते हैं। यूपीआई, आधार और जन धन जैसी परिवर्तनकारी नीतिगत पहलों के माध्यम से, देश ने वित्तीय समावेशन को अंतिम मील तक पहुंचाया है।

सरकार ने उपमोवताओं से बीआईएस प्रमाणित हेलमेट के उपयोग का आग्रह किया

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के उपभोक्ताओं से केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणित हेलमेट के उपयोग की अपील की। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बीआईएस प्रमाणीकरण के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सड़कों पर 21 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर



ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2024-25 में 500 से ज़्यादा हेलमेटों का परीक्षण करते हुए 30 से अधिक तलाशी और जब्तो अभियान चलाए।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नई दिल्ली में नौ निर्माताओं से 2,500 गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस

समाप्त हो चुके हैं या रह कर दिए गए हैं। चटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल

करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए बीआईएस मानकों (द्वि 4151:2015) के तहत प्रमाणित आईएसआई-अिच्छित हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का दूसरा सबसे बड़ा योगदान : जीतन राम मांझी

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला बताया है। उन्होंने इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में कहा कि एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) उत्पाद का 30.1 फीसदी हिस्सा है। ऊन्होंने कहा कि एमएसएमई देश में विनिर्माण का 35.4 फीसदी और निर्यात का 45.73 फीसदी हिस्सा है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने 3 जुलाई को मुंबई में विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कार्यालय का दौरा करके समीक्षा बैठक की। इसके संवाददाता सम्मेलन में कहा कि



गए उद्यम पोर्टल पर 3.80 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं। ऊन्होंने कहा कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने और ऊन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे औपचारिक लाभों तक पहुंच प्रदान

करने के लिए 11 जनवरी, 2023 को लॉन्च किए गए उद्यम सहायता पोर्टल के डेटाबेस में 2.72 करोड़ से अधिक इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि इन 6.5 करोड़ एमएसएमई इकाइयों

ने मिलकर आजतक 28 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम सहायता प्रदान

हरित विनिर्माण और संसाधन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एल्युमीनियम विजन दस्तावेज जारी

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में सतत एवं जिम्मेदार खनन पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एल्युमीनियम विजन दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज में 2047 तक एल्युमीनियम उत्पादन को छह गुना बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है। मंत्री रेड्डी ने कहा कि एल्युमीनियम विजन दस्तावेज एक आत्मनिर्भर और संसाधन-सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को सक्षम करने में एल्युमीनियम क्षेत्र

की रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश

डाला। खान मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस दस्तावेज में एल्युमीनियम उत्पादन को छह गुना



बढ़ाने, बॉक्साइट क्षमता को 150 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ाने, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है, जो

बढ़ाने, बॉक्साइट क्षमता को 150 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ाने, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है, जो

223.64 अंक टूट कर 83,015.83 अंक के स्तर तक गिर गया था। इसके बाद बाजार में खरीदारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में सुधार होने लगा। हालांकि दोपहर 2:30 बजे के बाद खरीदारी में अचानक काफी तेजी आ गई, जिसके कारण आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 238.39 अंक की मजबूती के साथ 83,477.86 अंक के स्तर पर पहुंच गया?। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 193.42 अंक की बढ़त के साथ 83,432.89 अंक के स्तर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर के पार



एजेंसी मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 जून को समाप्त हफ्ते में 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 702.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 1.01 अरब डॉलर घटकर 697.93 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 27 जून को समाप्त हफ्ते में स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.23 अरब डॉलर घटकर 84.5 अरब डॉलर रह गया।साथ ही

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 15.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.83 अरब डॉलर हो गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 17.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.62 अरब डॉलर हो गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर, 2024 के अंत में बढ़कर 704.88 अरब डॉलर के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

एलआईसी ने नव जीवन श्री और नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम स्कीम लॉन्च की

का उद्देश्य विशेष रूप से युवा पीढ़ी के व्यक्तियों की सभी जरूरतों को

प्रदान करने के साथ-साथ कोष बनाने के लिए है। एलआईसी का



पूरा करना है, जो अपने सपनों, लक्ष्यों, जिम्मेदारियों को पूरा करके सुरक्षा भी प्रदान करना चाहते हैं। इसी तरह नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जीवन बीमा

कहना है कि वर्तमान परिवेश में जब ब्याज दरें बहुत अस्थिर हैं, तो ये दोनों योजनाएं पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीकृत अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं।

एनपीएस के तहत मिलने वाले कर लाभ नई एकीकृत पेंशन योजना में भी मिलेंगे

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी कर लाभों को नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए भी लागू करने का फैसला लिया है। एनपीएस के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ यूपीएस पर लागू होंगे। नई पेंशन योजना को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इस वर्ष 19 मार्च को जरूरी नियम और विनियम जारी किये थे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब नवीनतम निर्णय के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत उपलब्ध समान कर राहत और प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें योगदान पर कटौती और अन्य कर-बचत लाभ शामिल हैं, जो इस योजना को वित्तीय रूप से अधिक

आकर्षक बनायेगा। यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाएगा और पारंपरिक एनपीएस के बजाय यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास है। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्वानुमानित और सुरक्षित अधिक आय प्रदान करना है। इस योजना में एक सुनिश्चित पेंशन के लिए सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 फीसदी और कर्मचारी 10 फीसदी योगदान देता है।

एनसीएच ने पिछले दो महीनों में उपमोवताओं को वापस किए 7.14 करोड़ रुपये

एजेंसी नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्थलाइन (एनसीएच) ने पिछले दो महीनों में उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपये का रिफंड उपलब्ध कराया है। ये महत्वपूर्ण निवारण 30 क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें रिफंड दावों से संबंधित 15,426 उपभोक्ता शिकायतों का प्राभावी ढंग से समाधान किया गया। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय के मुताबिक उल्लेखनीय रूप से ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक 8,919 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि सबसे अधिक 3.69 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड किया गया। इसके बाद टैबल और टूरिज्म सेक्टर का स्थान रहा, जिसमें 81 लाख रुपये का रिफंड किया गया। ई-कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें पूरे देश से आईं, जिनमें सबसे अधिक (1242) उत्तर प्रदेश से और यहां तक कि जैसिकसर और दादरा एवं नगर हवेली से जैसे छोटे क्षेत्रों से भी शिकायतें दर्ज की गईं, जो वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता निवारण मंच के रूप में एनसीएच की प्रभावशीलता को दर्शाता है। एनसीएच, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोगों पर बोझ को कम करते हुए उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से और सहूलपूर्व ढंग से हल करने में महत्वपूर्ण एवं मुकदमेबाजी भूमिका निभाती है।

प्रेग्नेंट हैं

सोनाक्षी सिन्हा

पति जहीर इकबाल संग चैट ने खोला राज, सामने आई सच्चाई

साल 2024 में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली थी. वे अपनी शादी की वजह से खूब चर्चा में रही थीं. उन्होंने एक्टर जहीर इकबाल संग सात फेरे लिए. दोनों ही शादी के बाद से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दोनों को कुछ मौकों पर साथ में भी स्पॉट किया गया है. सोनाक्षी सिन्हा हाल-फिलहाल में जब लाइमलाइट में आई तो उनको लेकर ये अफवाह भी खूब जोरों पर रही कि वे प्रेग्नेंट हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने हसबैंड जहीर इकबाल संग एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने बताया कि क्यों आखिर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर इतनी बातें हो रही हैं. सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर जहीर इकबाल संग अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें जहीर उनसे पूछते हैं- क्या तुम भूखी हो. जवाब में सोनाक्षी कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं. तुम मुझे खिलाना छोड़ो. फिर जहीर पूछते हैं कि मुझे लगा ये हॉलीडे था. इसके जवाब में सोनाक्षी कहती हैं कि मैंने अभी-अभी तो तुम्हारे सामने ही खाना खाया है. अब तुम बस करो. इसके बाद जहीर कहते हैं- आई लव यू. जवाब में सोनाक्षी कहती हैं- मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ.

जहीर जिस तरह से सोनाक्षी की केयर कर रहे हैं उसे लेकर ही लोगों को ये लग रहा है कि कहीं सोनाक्षी प्रेग्नेंट तो नहीं हैं. लेकिन अब सोनाक्षी ने इस बात का जवाब दे दिया है और बता दिया है कि फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सोनाक्षी और जहीर ने साल 2024 में शादी की थी. इस शादी में खास महमान नजर आए थे और इस दौरान की फोटोज भी खूब वायरल हुई थीं. हालांकि घरवालों के खिलाफ जाकर शादी करने की वजह से तनाव का माहौल भी नजर आया था.

वर्क फ्रंट पर क्या कर रही हैं सोनाक्षी सिन्हा ?

सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ के साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी सामंजस्य बनाकर चल रही हैं.

ओटीटी में धाकड़ जैसी दमदार सीरीज और हीरामंडी में डबल रोल करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा के हौसले काफी बुलंद हैं. साल 2024 में वे काकुड़ा और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों का हिस्सा रही थीं. साल 2025 की बात करें तो उनकी फिल्म निकिता रॉय रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज को फिलहाल बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से आगे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है.

सनी देओल-सलमान खान की फिल्म में की एक्टिंग, बिग बॉस का रहा हिस्सा, 8 सालों से कहां है ये एक्टर?



बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां दुनियाभर के लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आते हैं. कई एक्टर्स उनमें से ऐसे रहते हैं जो लंबी पारी खेलते हैं. वहीं कई एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका करियर उतना लंबा नहीं चलता लेकिन वे अपना नाम कमा ले जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने लीड रोल में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद इस एक्टर ने कई साइड रोल्स भी किए. ये एक्टर बिग बॉस का हिस्सा भी रहा. मगर अब इन्हें फिल्मों में आपने कम ही देखा होगा. हम बात कर रहे हैं आर्यन वैद की जो अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं. आइये जानते हैं कि आजकल एक्टर कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

कई कला में माहिर हैं आर्यन वैद

आर्यन वैद का जन्म 4 जुलाई 1976 को मुंबई में हुआ था. आर्यन एक मॉडल रहे हैं और उन्होंने साल 2000 में मिस्टर इंटरनेशनल का अवॉर्ड भी जीता था. उन्होंने शुरुआत में मुंबई में पृथ्वी थिएटरस के लिए भी कुछ स्टेज शोज किए. वे लाइफस्टाइल कॉलमनिस्ट भी रहे हैं और वे एक ट्रेंड शेफ भी हैं. आर्यन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत लीड एक्टर के तौर पर किए थे. इसके बाद वे फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में भी नजर आए. मगर उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली.

2003 में किया था करियर शुरू

साल 2003 में मार्केट फिल्म से लीड एक्टर के तौर पर आर्यन ने अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे चाहत एक नशा, दुबई बाबू, फन, नाम गुम जाएगा, एक ज़िद एक जान, मनोरंजन, देशद्रोही, अपने और वीर जैसी फिल्म में काम किया था. वीर फिल्म में वे सलमान खान के साथ नजर आए थे वहीं अपने फिल्म में वे सनी देओल के साथ नजर आए थे. उन्होंने वेलकम, रब से सोना इश्क, उड़ान और संतोषी मां जैसे सीरियल्स में काम किया.

पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से हैं दूर

आर्यन वैद पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से एकदम दूर हैं. उनकी पिछली फिल्म राजा थी जो साल 2019 में आई थी. लेकिन ये एक भोजपुरी फिल्म थी. वहीं वे 2017 में पिछली बार संतोषी मां नाम के सीरियल में इंद्र देव का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे. मगर पिछले 8 सालों से वे वर्क फ्रंट पर एक्टिव नजर नहीं आए हैं. लेकिन एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जरूर चर्चा में आए थे. साल 2018 में पहली शादी टूटने के बाद आर्यन ने 2022 में फ्लोरीडा की महिला अरिन एरिन वॉरेन से शादी रचा चुके हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ फोटोज भी वायरल हैं.

28 साल पहले इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म में विलेन बनी थीं काजोल, बाँबी देओल की कट दी थी सिट्टी-पिट्टी गुल



27 साल पहले बॉलीवुड की एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. उस फिल्म के गाने, कहानी और डायलॉग्स सब कमाल थे लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात कर हुई कि फिल्म में काजोल का निगेटिव रोल था जो दमदार रहा. फिल्म में काजोल के अलावा एक और हीरोइन थी जबकि एक लीड हीरो था. फिल्म की कहानी कुछ ऐसी लिखी गई है कि आखिर तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मेन विलेन आखिर है कौन ? फिल्म गुप्त: द हिडेन ट्रुथ में लीड एक्टर बाँबी देओल थे और ये उनकी उन फिल्मों में एक थी, जो जबरदस्त हिट साबित हुई थी. वहीं दूसरी हीरोइन मनीषा कोईराला थीं और इस फिल्म के जरिए उनके करियर में एक और सुपरहिट जुड़ गई थी. चलिए फिल्म गुप्त: द हिडेन ट्रुथ की कहानी से लेकर इसके डायरेक्टर, स्टारकास्ट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर विस्तार से चर्चा करते हैं.

‘गुप्त: द हिडेन ट्रुथ’ की कमाई कितनी हुई थी ?

4 जुलाई 1997 को रिलीज हुई फिल्म ‘गुप्त: द हिडेन ट्रुथ’ के डायरेक्टर राजीव राय थे. फिल्म के प्रोड्यूसर राजीव राय और गुलशन राय थे. वहीं फिल्म में विजु शाह का म्यूजिक डायरेक्शन था. फिल्म की लीड स्टारकास्ट बाँबी देओल, काजोल और मनीषा कोईराला थे. वहीं परेश रावल, प्रेम चोपड़ा, दिलीप ताहिल, रजा मुराद, ओम पुरी और कुलभूषण खरबंदा जैसे स्टार्स ने भी अहम किरदार निभाए थे. अगर कमाई की बात करें तो Sacnilk के मुताबिक, फिल्म का बजट 9 करोड़ था जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 33.15 करोड़ था. इस फिल्म का वर्डिक्ट हिट साबित हुआ था.

किस ओटीटी पर देख सकते हैं ‘गुप्त: द हिडेन ट्रुथ’ ?

फिल्म गुप्त: द हिडेन ट्रुथ में लगभग 8 गाने थे जबकि इसमें ‘गुप्त टाइल सॉन्ग’, ‘दुनिया हसीनो का मेला’, ‘मेरे ख्वाबों में’, ‘मेरे सनम’ और ‘ये प्यासी मोहब्बत’ जैसे गाने हिट हुए थे. फिल्म में साहिल सिन्हा (बाँबी देओल) के ऊपर अपने फादर की हत्या का आरोप लग जाता है. लेकिन वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कई कदम उठाता है. वहीं साहिल को जेल से बाहर आने के लिए शीतल (मनीषा कोईराला) उसकी मदद करती है. इसके बाद कहानी को मोड़ लेती है वो बहुत दिलचस्प है. वहीं ईशा दिवान (काजोल) साहिल को पाने के लिए हर हद पार करती हैं.

ऐश्वर्या राय

की इन आदतों को बर्दाश्त करते हैं अमिताभ-अभिषेक, ननद को भी नहीं भाती भाभी की ये बात

अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं. जब भी अभिषेक की कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, बिग बी अपने बेटे के काम की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं. वहीं जब एक बार महानायक से उनकी बहू ऐश्वर्या राय की आदतों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने खुलकर बताया कि उन्हें उनकी कौन-सी आदत नहीं पसंद है. ऐश्वर्या और अभिषेक पिछले साल अपने तलाक की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. हालांकि ये सभी खबरें अफवाह निकलीं. लेकिन अब अमिताभ और अभिषेक ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए नजर नहीं आते हैं. दरअसल एक बार करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के मंच पर अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ शिरकत की थी. ये साल 2010 तक की बात है, जब बाप-बेटी की जोड़ी पहली बार साथ में किसी चैट शो पर पहुंची थी. इस दौरान दोनों ने अपने परिवार और घर के सदस्यों के बारे में कई सारी बातें भी की थीं. शो के रेपिड फायर राउंड के दौरान करण ने अमिताभ से पहले सवाल किया कि उन्हें

अभिषेक की कौन सी आदत नहीं पसंद ?

अभिषेक-ऐश्वर्या की आदतों पर बोले अमिताभ

सवाल का जवाब देते हुए बिग बी ने तुरंत कहा, उन्हें अभिषेक का हिंदी में कम बातें करना पसंद नहीं आता. इसके बाद करण ने उनसे अगला सवाल पूछा कि उन्हें बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन सी बात पसंद नहीं आती ? इसके जवाब में दिग्गज एक्टर ने कहा कि उनका टाइम मैनेजमेंट. अमिताभ और श्वेता के इस एपिसोड के ऑन एयर होने के 10 साल बाद, करण के चैट शो पर श्वेता और अभिषेक भी पहुंचे थे.

ऐश्वर्या की इस आदत को बर्दाश्त करते हैं अभिषेक

10 साल बाद करण जौहर ने अभिषेक और श्वेता के सामने पुराने सवाल दोहराए थे. पहले अभिषेक से करण ने पूछा कि उन्हें ऐश्वर्या की क्या चीज पसंद है. जवाब में एक्टर ने कहा, कि वो मुझसे प्यार करती हैं. इसके बाद उनसे अगला सवाल पूछा गया कि उन्हें ऐश्वर्या की किस आदत को बर्दाश्त करना पड़ता है.



बिरसा टाइम्स देश का सर्वाधिक प्रसारित रविवारीय अखबार है। अपनी खोजपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक खबरों के कारण बिरसा टाइम्स ने मीडिया- जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्ष 1980 से शुरू हुआ बिरसा टाइम्स का सफरनामा इसके पाठकों के निरंतर स्नेह और समर्थन के चलते आज भी उसी तेवर के साथ जारी है।

राँची और दिल्ली के साथ-साथ अब बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से प्रकाशित होने जा रहा है।

बिरसा टाइम्स

देश का सर्वाधिक प्रसारित नंबर-1 रविवारीय अखबार

जन सम्पर्क विभाग में विशाल भ्रष्टाचार का वट वृक्ष

विशेष संपादक द्वारा

रांची: रांची के आसपास स्थित बिरसा टाइम्स की रांची कार्यालय में 06 जुलाई 2025 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे।

“ जब झारखंड और बिरसा एक साथ थे तब पांडे अपने पिता के साथ पटना में मलवीर मंदिर में साफ-साफाई का काम करता था और पांडे जी के पिता मंदिर के सचिव आईपीएस स्वर्गीय आचार्य किशोर कुमाल जी के घर पर पूजा पाठ करते थे एवं मलवीर मंदिर में श्री काम करते थे और उसी समय अवधि में पांडे बिरसा सरकार में दैनिक मजदूर में बसली लेकर पीरे-पीरे आई ई एस पदाधिकारी के घर पर कप-लेट साफ कर प्रशासक निदेशक तक पहुंच गए। श्री पांडे को हिंदी और अंग्रेजी में एक लाइन भी लिखने नहीं आता था। इनका साथ का साथ फाइल का काम के नीचे वाले अधिकारी लिखते थे और इस काम में उप निदेशक श्री शालिनी वर्मा और वर्तमान में बोकायों के उपायुक्त श्री अजय नाथ झा साथ फाइल का काम करते थे। दोनों के दोनों से पांडे के कार्यालय से लेकर आवास तक 11:00 बजे तक मजदूर लेते रहते थे और इसमें अपनी कुशलता से श्री झा ने उपायुक्त पद पर पहुंच गए। ऐसे पांडे कभी भी अपनी पत्नी को अपने आवास में नहीं रखते थे और पांडे के समय में सिर्फ सिर्फ उसके पिता ही रहते थे और श्री पांडे के समय में जनसम्पर्क विभाग में भ्रष्टाचार का पेड़-पौधा लगन। शुरू हुआ और अब वर्तमान में जनसम्पर्क विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा वरगढ़ का पेड़ से चुका है।



बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे।

बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे।

बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में बिरसा टाइम्स के रांची कार्यालय के प्रमुख अधिकारी और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी शामिल थे।

बिरसा टाइम्स देश का विश्वास पत्रकारिता के उन मूल्यों में हैं जो आम आदमी की चिंताओं और सरोकारों को आवाज देते हैं। इसीलिए बिरसा टाइम्स लोगो के बीच इस लम्बी यात्रा में भी अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने में कामयाब रहा है। अपने खास कंटेंट, गंभीर राजनैतिक विश्लेषण, अलग अंदाज और सुन्दर छपाई के चलते बिरसा टाइम्स को सम्मान-जनक स्थान मिला है। शायद इसीलिए बिरसा टाइम्स के पाठक वे युवा और संवेदनशील लोग हैं जो न केवल देश के बारे में सोचते हैं बल्कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं।

सत्य और निष्पक्ष समाचारों के लिए पढ़ें !

सम्पर्क सूत्र :-



aadivasiexpress@gmail.com
birsatimes@gmail.com



8084674042



6202611859
8084674042